भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2744
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: न्यूनतम समर्थन मूल्य
2744. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेरः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसानों को लाभान्वित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संबंध में उनकी मांगों को समय पर और कुशल तरीके से पूरा किया जाएगा क्योंकि देर होने से काफी संकट पैदा हो गया है और कई किसानों ने विरोध करना जारी रखा हुआ है;
(ख) इस कानून को लागू करने में देरी के क्या कारण हैं और इसके कार्यान्वयन के लिए संभावित समय-सीमा क्या है;
(ग) कार्यान्वयन प्रक्रिया के संबंध में किसानों और उनके नेताओं द्वारा व्यक्त चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) क्या सरकार जारी संकट का समाधान खोजने के लिए किसानों के साथ परामर्श करके हल निकालने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों पर चिंतन करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के लिए पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 50 प्रतिशत के न्यूनतम रिटर्न के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी।

सरकार निर्दिष्ट खरीद एजेंसियों के माध्यम से कृषि फसलों की खरीद की पेशकश करती है और किसानों के पास अपनी उपज को सरकारी एजेंसियों को या खुले बाजार में बेचने का विकल्प होता है, जो भी उनके लिए लाभदायक हो।

सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। जब दलहन, तिलहन और कोपरा का बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है, तब संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से इन उत्पादों की खरीद, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समग्र योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाती है। पीएम-आशा योजना के तहत खरीद एजेंसियां भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) हैं। सरकार द्वारा कपास और पटसन की खरीद भी क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है।

बढ़े हुए एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हुआ है, जो खरीद के आंकड़ों और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि से स्पष्ट है। वर्ष 2024-25 (फसल वर्ष) के दौरान की गई खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

कुल खरीद (एलएमटी में)	कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)
1,223	3.47

भारत सरकार उपयुक्त नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करके किसानों के कल्याण के लिए की गई भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहलें निम्न प्रकार है:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)- ऑयल पाम
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
4. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
5। परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीआई)
6. सॉइल हेल्थ एंड फर्टीलिटी (एसएचएंडएफ)
7. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
8. कृषि वानिकी
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
10. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
11. बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
12. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
13. राष्ट्रीय बांस मिशन
14. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
16. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
17. इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग (आईएसएएम)
18. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
19. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
20. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
21. प्रधानमंत्री अन्नदता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
22. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएस)
23. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
24. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
25. स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
26. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
27. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन

*****